



नवीन वैश्विक परिदृश्य के मध्य भारतीय विदेश नीति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुरेश कुमार ¹

¹ पूर्व सहायक आचार्य-राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय(राजसेस अधीन) शिवगंज, जिला सिरौही

ABSTRACT:

किसी भी देश की विदेश नीति विशिष्ट आन्तरिक व बाह्य वातावरण के स्वरूप द्वारा काफी हद तक निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त उसकी ऐतिहासिक विरासत या धरोहर, व्यक्तित्व विचारधाराएँ, विभिन्न संरचनाओं आदि का प्रभाव भी उस पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जैसे विदेश नीति राष्ट्रीय हितों, अधिकारों, मूल्यों, सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों का एक जोड़ है। प्रत्येक देश, अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को संचालित करने हेतु उनका प्रतिपादन करता है। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश (वातावरण) के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है ताकि वह अन्य देशों के व्यवहार में आमचूल परिवर्तन ला सके, उसे प्रभावित कर अपने नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जैसे विदेश नीति के निर्माण एवं संचालन में विविध निर्धारक तत्वों, संस्थाओं, प्रणालियों एवं व्यक्तिगत कारकों की अहम भूमिका रहती है। जैसे विदेश नीति एक गहरी प्रक्रिया है। इसमें नीतिकार या कूटनीतिकार विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षार्थ करने के लिए अपने-अपने स्तर पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने हेतु प्रयासरत दिखाई देते हैं।

भारत की विदेश नीति अन्य देशों की विदेश नीतियों की तरह राष्ट्रीय हितों, अधिकारों, एक-दूसरे के प्रति प्रेम-भाव, सौहार्द, सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भौगोलिक परिस्थितियों एवं मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों द्वारा निर्धारित हुई है, लेकिन विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक (तत्त्व) भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि प्रत्येक देश का अपना एक विशिष्ट इतिहास, खान-पान, वेशभूषा, परिवेश एवं संस्कृति होती है, जो विदेश नीति के निर्माण को प्रभावित करती है। भारतीय परिदृश्य पर यदि विचार किया जाए तो भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक विश्व में विविध परिवर्तन आ चुके हैं। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के द्विध्रुवीय विश्व से लेकर अमेरिकी आधिपत्य के एक संक्षिप्त एकध्रुवीय काल तक और अब चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विध्रुवीय प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ने से लेकर बहुध्रुवीयता के एक भ्रम तक विश्व ने कई स्वरूप देखे हैं।

आज के इस विशृंखल विश्व में भारत को अपनी विशिष्ट विदेश नीति पहचान को परिभाषित करने और नैतिक मूल्यों के साथ राष्ट्रीय हित को संतुलित करने के लिये अपनी संलग्नता की रूपरेखा को आकार देने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अतः नवीन वैश्विक परिदृश्य के मध्य भारतीय विदेशनीति विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर हैं।

KEYWORDS:

PAPER ACCEPTED DATE:

19th March 2024

PAPER PUBLISHED DATE:

21st March 2024

प्रस्तावना:-

भारत की विदेश नीति अन्य देशों की विदेश नीतियों की तरह राष्ट्रीय हितों, अधिकारों, एक-दूसरे के प्रति प्रेम-भाव, सौहार्द, सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक परिस्थितियों एवं मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों द्वारा निर्धारित हुई हैं, लेकिन विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक (तत्त्व) भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना एक विशिष्ट इतिहास, खान-पान, वेशभूषा, परिवेश एवं संस्कृति होती है, जो विदेश नीति के निर्माण को प्रभावित करती है। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में राजनीतिक संस्कृति के शब्दों पर पहले प्रकाश डाल लेना उचित रहेगा, क्योंकि इन दोनों कारकों या शब्दों में भारतीय विदेश नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भली-भाँति समझ सकते हैं यथा-राजनीतिक संस्कृति का विचार यह मानकर चलता है कि राजनीतिक आचरण को निर्दिष्ट करने वाली सभी भावनाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय और भावबोध केवल अचानक इकट्ठे हो जाने वाले मनोभाव कहे गये हैं किन्तु उनकी अपनी एक व्यवस्था है, जो आपसी समन्वय के साथ पारस्परिक ढंग से सशक्त बनती है। राजनीतिक संस्कृति का संबंध समाज, राज्य एवं देश की जनता की अभिरूचियाँ, विश्वास, भावनाओं और मूल्यों से होता है और इनकी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से घनिष्ठता होती है। सामान्य रूप में सभी मानवों की प्रकृति भले ही समान होती है किन्तु अपने-अपने भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेशों में इनमें अन्तर भी होता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश अर्थात् राष्ट्र की कूटनीतियों, संबंधों का, वहाँ के रहन-सहन, परिवेश, इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था में अन्तर पाया जाता है।" अर्थात् प्रत्येक देश अपने इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक प्रभुत्व अर्थात् राष्ट्रों में अपनी अलग पहचान बनाने हेतु कटिबद्ध प्रतीक होते हैं। सत्ता के सहज, संचालन में राजनीतिक व्यवहार अथवा राजनीतिक संस्कृति का विशेष स्थान है।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्य

प्रत्येक राष्ट्र के समान ही भारत की विदेश नीति का प्रमुख और प्राथमिक उद्देश्य अपने 'राष्ट्रीय हितों' को सुरक्षित करना है।

भारत की विदेश नीति का पहला और प्रमुख उद्देश्य किसी अन्य देश की तरह अपने हितों, अधिकारों, अस्मिता, अखण्डता को सुरक्षित करना है। किसी देश की अस्मिता एवं अखण्डता और राष्ट्रीय हितों का दायरा काफी व्यापक एवं विस्तृत होता है; इन्हें किन्हीं शब्दों में व्याख्या करना कठिन हो सकता है फिर भी भारत की विदेश नीति का पहला उद्देश्य क्षेत्रीय या भौगोलिक अखण्डता की रक्षा करना, ऊर्जा संसाधनों, सुरक्षा व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, अर्थात् भारत को पारम्परिक और गैर-पारम्परिक खतरों से बचाना होता है।

सभी देशों के लिये 'राष्ट्रीय हित' का दायरा अलग होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिये हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा-पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं।

विभिन्न परियोजनाओं जैसे- मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिये भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और तकनीकी की जरूरत है।

भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहाँ उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है, इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी है।

इस प्रकार भारत की विदेशनीति का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्र को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करना, समावेशी वातावरण का विकास करना जो प्रत्येक व्यक्ति के लाभ से युक्त हो, वैश्विक पटल पर भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक अस्तित्व की स्थापना करना, विदेश में भारतीय प्रवासियों को उनके हितों से जोड़ना, विश्व कल्याण एवं भारतीय सुरक्षा व्यवस्था और भारत के सर्वांगीण विकास के साथ भारतीय जनता के कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत रहना, वैश्विक पटल पर मधुर एवं मृदुल विदेश नीति का पालन करना आदि है।

भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्त

भारत की विदेश नीति के प्रमुख पांच सिद्धान्त हैं यथा-

- एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान।
- पारस्परिक आक्रमण न करना।
- परस्पर हस्तक्षेप न करना।
- समता और आपसी लाभ।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

इस प्रकार भारत ने सदैव अपने राष्ट्र की अखंडता, जीवन मूल्यों, आदर्शों, सिद्धान्तों और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विदेशनीति में और साथ ही विश्व के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर स्वतंत्र रूप से विदेश नीतियों का परिपोषण करते हुए संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है।

वर्तमान भारत की विदेश नीति की बदलती दिशा

वर्तमान परिदृश्य में सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिये सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीकी, प्रौद्योगिकीय ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत विकसित देशों के साथ प्रयत्नशील है।

भारत ने वैश्विक पटल पर अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि बड़े से बड़े खतरे और चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी वह साहस नहीं छोड़ता। कोरोना जैसी वैश्विक समस्या के समक्ष भी भारत डटकर मुकाबला करता रहा जिसमें उसने न केवल स्वयं ही वरन विश्व की भी सहायता की। इस संदर्भ में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने, ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होते हुए कहा था कि, भारत, कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिये करीब 85 देशों को दवाओं और अन्य उपकरणों के माध्यम से मदद पहुँचा रहा है, ताकि ये देश भी महामारी का मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त कर सकें।

प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क (SAARC) देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया तत्पश्चात उन्होंने G-20 देशों के प्रमुखों के साथ भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा। इन दोनों ही शिखर सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 की महामारी से निपटने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया। जबकि एक समय पर ये सभी मंच नेतृत्वविहीन लग रहे थे।

इन कूटनीतिक अनुबंधों के अतिरिक्त, भारत ने 'विश्व का दवाखाना' की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का भी सतत प्रयत्न जारी रखा है। इसके लिये भारत ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन (HCQ) का निर्यात पूरी दुनिया को किया है।

इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रत्येक पटल पर भारत ने अपनी विदेश नीति को सुदृढ़ किया है चाहे वह स्वास्थ्य की दृष्टि से हो अथवा दवाईयाँ हों।

वर्तमान सरकार ने पूर्व में शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी से सटे बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी बिम्स्टेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। इसमें भारत की 'प्रथम पड़ोस' और 'एक्ट ईस्ट' नीति भी एकाकार होती है। इसके उलट सार्क का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्स्टेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है।

वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ज्ञात होता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश कर रहे हैं।

आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या को जड़ सहित समाप्त करने के लिए भारत ने विदेश नीतियों

में सुधार करते हुए पुलवामा अटैक के उपरांत सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभूतपूर्व कदम उठाकर दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस प्रकार के सख्त कदमों ने भारत की विदेश नीति को परिवर्तित और नवीन स्वरूप प्रदान किया है।

भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ अपने राजनीतिक स्वरूप को स्थिर करने के लिए उसे तमिल राजनीति से अलग कर एक सांस्कृतिक सौंदर्य प्रदान करते हुए एकता के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यह उसकी वैश्विक नीति की उत्कृष्टता का उदाहरण है।

इस प्रकार भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी वैश्विक नीति को सौंदर्य, सक्षमता, सुदृढ़ता और स्थिरता प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों जैसे जीवन मूल्यों, आदर्शों, अभिवादन शैली, क्षमाशील वृत्ति, परोपकारी दृष्टि, दुष्टता हेतु दण्ड नीति आदि का प्रयोग कर वैश्विक पटल पर विदेश नीति को एक नवीन स्वरूप के साथ स्थापित कर दिया है।

नवीन वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति :-

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अमरीका राष्ट्रपति के साथ कुछ समय पूर्व ही सम्पन्न हुई मुलाकात (2021-22) भारत की विदेश नीति में एक मील का पत्थर साबित हुई। इतनी ही महत्वपूर्ण थी चौपक्षीय सुरक्षा वार्ता क्योंकि यह कोविड-19 संकटकाल के बाद भारत की आर्थिक तथा रणनीतिक भूमिका को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हुई थी।

भारत अपनी सूझबूझ से विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता बना। जिसने 'मैत्री' कार्यक्रम के तहत वैश्विक स्तर पर गरीब देशों को कोविड वैक्सीन उपदेशोंकरवाई। विभिन्न संकटों के आने पर भी व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी वार्ता के दौरान कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित सभी मुद्दों को सुलझा लिया। अमरीकी और भारतीय नेताओं ने मिलकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को खारिज किया, जो क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को अतिरिक्त बढ़ावा देती है, इस संदर्भ में उन्होंने आतंकवादी समूहों को सामान, वित्तिय तथा सैन्य सहायता रोकने की जरूरत को महत्व दिया। एक विशेषज्ञ के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की 'एक्ट ईस्ट' नीति उचकी विदेश नीति की सबसे बड़ी पहल है।

वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने हेतु भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा क्षेत्र में संबंध स्थापित किये हैं- "अमेरिका राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमति बनी है।"

अतः भारत-अमेरिका संबंधों के विभिन्न क्षेत्र रक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, आर्थिक, प्रवासी भारतीय, हिन्द-प्रशात क्षेत्र आदि को लेकर दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। जो भारत की दूरदर्शिता को अभिव्यक्त करता है।

रूस के साथ संबंध, भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण स्तम्भ है और रूस, भारत का दीर्घकाल से समय की कसीटी पर खरा उतरा भागीदार देश है। वैसे भारत और रूस के रिश्तों में तमाम सकारात्मक संकेतों के बावजूद हमें उनकी अहमियत को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं आंकना चाहिए। खासतौर से तब और जब हम अमेरिका और उसके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वियों चीन और रूस के बीच रिश्तों के हवाले से भविष्य के अन्तराष्ट्रीय समीकरणों को देखते हैं यथा "रूस के राष्ट्रपति ब्लाडिमीर पुतिन के भारत दौर से दोनों देशों के रिश्तों में हाल के दिनों में पैदा हुई कुछ नीतिगत दूरियों को भरने में काफी मदद मिली है।

अतः यह तो निश्चित है कि भारत की विदेशनीति वर्तमान परिदृश्य में एक नए रूप में प्रस्तुत हुई है। जिसने विदेशों के साथ अपने मित्र संबंधों को अत्यधिक प्रगाढ़ किया है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहुंच को सुदूर क्षेत्रों से जोड़ा है जो भारत और भारतीय जनता के कल्याण के लिए अत्यधिक आवश्यक है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है भारत के लिए अच्छे मित्रों की आपसी मित्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि वाशिंगटन और मांस्को के बीच के संबंधों में सुधार होता है, तो वृहत शक्ति समीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण के प्रति व्यापक रूप से भिन्न दृष्टिकोण से उत्पन्न संरचनात्मक बाधाओं को कम किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यही है कि इन दोनों शक्तियों के बीच कम संघर्षपूर्ण संबंध भारत के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसके अलावा शक्ति के लिए अमेरिका चीन के बीच होड या चीन के साथ रूस के गहरे होते संबंध भारत के लिए अधिक मायने नहीं रखते अगर चीन के साथ उसके संबंध अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर होते हैं।

अंततः यह है कहा जा सकता है कि भारत नवीन वैश्विक परिदृश्य के मध्य अपनी विदेश

नीतियों के माध्यम से विश्व पटल पर अपने अस्तित्व को एक बार पुनः स्थापित करने में सक्षम हो पाया है। आज उसने प्रत्येक क्षेत्र में अपने सूझबूझ और ऋषि सभ्यता का सहारा लेकर विश्व में अपना स्थान सर्वोपरि कर दिखाया है। आज भारत वैश्विक पटल पर स्वयं को एक सशक्त रूप प्रदान करने में सक्षम हो सका है। और उसकी सुदृढ़ विदेशनीति उसे एक दिन शीघ्र ही वैश्विक पटल पर प्रथम स्थान प्रदान करेगी।

REFERENCES

1. वैदिक, डॉ. वेदप्रताप-भारतीय विदेश नीति के नये दिशा संकेत, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली-1980.
2. महेन्द्र कुमार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा-3, 1997.

3. प्रो. बी. एम. जैन. प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, राजस्थान हिन्दी अकादमी, जयपुर-2000.
4. डॉ. बी. एल. फडिया अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, आगरा-2001,
5. प्रो. बी. एम. जैन अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 2013.
6. घई, यू.आर. “भारतीय विदेश नीति” न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर, 2013.
7. शर्मा, डॉ. मथुरालाल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (1945 से अब तक) कॉलेज कम डिपो, जयपुर 2014.
8. घोष, पिऊ, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध,” पी.एच.आई. लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2015.